



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 85] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 19, 1982/फाल्गुन 28, 1903  
No. 85] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 19, 1982/PHALGUNA 28, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

## गृह मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1982

ता० का० नि० 256 (अ):—राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई निम्न-  
लिखित उद्घोषणा सर्व माधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है :

यतः मुझे भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को असम राज्य  
के राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और मुझे प्राप्त इस रिपोर्ट और  
अन्य सूचना पर विचार करने के बाद मेरा समाधान हो गया है कि ऐसी  
स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिसमें कि असम राज्य का शासन भारत के  
संविधान (जिसे इसमें इसके पश्चात् "संविधान" कहा गया है) के उपबंधों  
के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है ;

अतः अब मैं, संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का  
मया उम निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग  
करते हुए एतद्द्वारा उद्घोषणा करता हूँ कि मैं :—

(क) उक्त राज्य की सरकार के सभी कृत्य और उस राज्य के  
राज्यपाल में निहित या उनके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियां  
भारत के राष्ट्रपति के रूप में स्वयं संभालता हूँ ;

(ख) घोषित करता हूँ कि उक्त राज्य के विधान मंडल की शक्तियां  
संसद द्वारा या संसद के प्राधिकार के अधीन प्रयोक्तव्य होंगी ;  
और

(ग) निम्नलिखित आनुपूर्विक और परिणामिक उपबन्ध करना हूँ  
जो इस उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए  
मुझे आवश्यक या वांछनीय प्रतीत होती हों अर्थात् :—

(1) पूर्वोक्त इस उद्घोषणा के उपर्युक्त खंड (क) के आधार  
पर मेरे द्वारा स्वयं संभाले गए कृत्यों और शक्तियों का  
प्रयोग करने में मेरे लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप  
में उम सीमा तक जिस तक मैं ठीक समझू, उक्त राज्य  
के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करना विधिपूर्ण होगा ;

(2) उस राज्य के सम्बन्ध में संविधान के निम्नलिखित  
उपबंधों के प्रवर्तन को एतद्द्वारा निर्व्विन किया जाता  
है अर्थात् :—

अनुच्छेद 3 के परन्तुक का उक्त भाग जितने  
का सम्बन्ध राष्ट्रपति द्वारा राज्य के विधान मंडल को  
निर्देश करने से है ;

अनुच्छेद 151 के खंड (2) का उक्त भाग  
जितने का संबंध भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक  
द्वारा राज्यपाल को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के राज्य  
विधान मंडल के समक्ष रखे जाने से है ;

अनुच्छेद 163 और 164 ;

अनुच्छेद 166 के खंड (3) का उक्त भाग  
जितने का संबंध राज्य सरकार के कार्यों का मंत्रियों  
के बीच आबंटन से है ;

अनुच्छेद 167 और अनुच्छेद 169 के खंड (1) का उतना भाग जितने का संबंध राज्य की विधान सभा द्वारा मकान के पारित किए जाने से है ;

अनुच्छेद 174 का खंड (1) और खंड (2) का उपखंड (क); अनुच्छेद 175 से 178 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं), अनुच्छेद, 179 का खंड (ख) और (ग) और उस अनुच्छेद का प्रथम परन्तुक और अनुच्छेद 180 और 181 ;

अनुच्छेद 186 का उतना भाग जितने का संबंध विधान सभा के उपाध्यक्ष के संबलनों और भत्तों से हैं अनुच्छेद 188, 189, 193, 194, 195 तथा 196, अनुच्छेद 198 अनुच्छेद 199 का खंड (3) और खंड (4) ;

अनुच्छेद 202 के खंड (3) का उतना भाग जितने का संबंध विधान सभा के उपाध्यक्ष के संबलनों और भत्तों से हैं; अनुच्छेद 208 से 211 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं), अनुच्छेद 213 के खंड (1) का परन्तुक और खंड (3) का परन्तुक; और

अनुच्छेद 323 के खंड (2) का उतना भाग जितने का संबंध ज्ञापन सहित रिपोर्ट को राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखे जाने से हैं ;

- (3) उक्त राज्य की विधान सभा एतद्वारा भंग की जाती है।
- (4) संविधान में राज्यपाल के प्रति किसी निदेश का अर्थ उस राज्य के संबंध में राष्ट्रपति के प्रति निदेश लगाया जाएगा और उसमें राज्य के विधान मंडल या सदनों के प्रति किसी निदेश का जहां तक उसका संबंध उसके कृत्यों और उसकी शक्तियों से है अर्थ जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो संसद के प्रति निदेश लगाया जाएगा और विशिष्टतया अनुच्छेद 213 में राज्यपाल और राज्य के विधान मंडल या सदन के प्रति निदेश का अर्थ क्रमशः राष्ट्रपति और संसद या उसके सदनों के प्रति निदेश लगाया जाएगा।

परन्तु इसमें की कोई बात अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155 से अनुच्छेद 159 तक ( जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं ), अनुच्छेद 299 और अनुच्छेद 361 तथा द्वितीय अनुसूची के पैरा 1 से 4 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं), के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी और न राष्ट्रपति को इस खंड के उपखण्ड (1) के अधीन उस सीमा तक जहां तक वे ठीक समझें उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करने से निवारित करेगी ;

- (5) संविधान में राज्य के विधान मंडल या उसके द्वारा बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति किसी निर्देश का ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानो उनके अंतर्गत इस उद्घोषणा के आधार पर संसद द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा या संविधान के अनुच्छेद 357 के खंड (1) के उपखंड (क) और असम राज्य में यथा प्रवृत्त असम साधारण खंड अधिनियम 1915 (1915 का असम अधिनियम 2) में निश्चित अन्य प्राधिकारी द्वारा राज्य के विधान मंडल की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति निदेश है और साधारण खण्ड अधिनियम 1897 ( 1897 का 10) का उतना,

भाग जितना कि राज्य विधियों पर लागू हैं ; ऐसी किसी अधिनियम या विधि के बारे में ऐसे प्रभावी हंगामा माना यह उस राज्य विधान मंडल का अधिनियम हो।

नई दिल्ली,  
19 मार्च, 1982

नीलम संजीव रेड्डी,  
राष्ट्रपति

[सं० 5/11013/3/82- सी० एम० आर०]

त्रिवेणी नाथ चतुर्वेदी, सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 1982

**G.S.R. 256(E).**—The following proclamation by the President is published for general information :—

Whereas, I, Neelam Sanjiva Reddy, President of India, have received a report from the Governor of the State of Assam and after considering the report and other information received by me, I am satisfied that a situation has arisen in which the Government of Assam cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution of India (hereinafter referred to as "the Constitution") ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by article 356 of the Constitution and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby proclaim that I—

- assume to myself as President of India all functions of the Government of the said State and all powers vested in or exercisable by the Governor of that State;
- declare that the powers of the Legislature of the said State shall be exercisable by or under the authority of Parliament; and
- make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary or desirable for giving effect to the objects of this Proclamation, namely :—
  - in the exercise of the functions and powers assumed to myself by virtue of clause (a) of this Proclamation as aforesaid, it shall be lawful for me as President of India to act to such extent as I think fit through the Governor of the said State;
  - The operation of the following provisions of the Constitution in relation to that State is hereby suspended, namely :—

so much of the proviso to article 3 as relates to the reference by the President to the Legislature of the State ;

so much of clause (2) of article 151 as relates to the laying before the Legislature of the State of the reports submitted to the Governor by the Comptroller and Auditor-General of India;

articles 163 and 164 ;

so much of clause (3) of article 166 as relates to the allocation among the Ministers of the business of the Government of the State ;

article 167 and so much of clause (1) of article 169 as relates to the passing of a resolution by the Legislative Assembly of a State ;

class (1), and sub-clause (a) of clause (2) of article 174; articles 175 to 178 (both inclusive) ; clauses (b) and (c) of article 179 and the first proviso to that article and articles 180 and 181 ;

so much of article 186 as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker of the Legis-

lative Assembly articles 188, 189, 193, 194, 195 and 196; article 198; clauses (3) and (4) of article 199 ;

so much of clause (3) of article 202, as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker of the Legislative Assembly; articles 208 to 211 (both inclusive) the proviso to clause (1) and the proviso to clause (3) of article 213; and

so much of clause (2) of article 323 as relates to the laying of the report with a memorandum before the Legislature of the State;

(iii) the Legislative Assembly of the said State is hereby dissolved;

(iv) any reference in the Constitution to the Governor shall in relation to the said State be construed as a reference to the President, and any reference therein to the Legislature of the State or the Houses thereof shall, in so far as it relates to the functions and powers thereof, be construed, unless the context otherwise requires, as a reference to Parliament, and, in particular, the references in article 213 to the Governor and to the Legislature of the State or the Houses thereof shall be construed as reference to the President and to Parliament or the Houses thereof respectively ;

Provided that nothing herein shall affect the provisions of article 153, articles 155 to 159 (both inclusive), article 299 and article 361 and paragraph 1 to 4 (both inclusive) of the Second Schedule or prevent the President from acting under sub-clause (i) of this clause to such extent as he thinks fit through the Governor of the said State;

(v) any reference in the Constitution to Acts or laws of or made by the Legislature of the State shall be construed as including a reference to Acts or laws made, in exercise of the powers of the Legislature of the State, by Parliament by virtue of this Proclamation, or by the President or other authority referred to in sub-clause (a) of clause (1) of article 357 of the Constitution, and the Assam General clauses Act, 1915 (Assam Act 2 of 1915) as in force in the State of Assam and so much of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) as applies to State laws, shall have effect in relation to any such Act or law, as if it were an Act of the Legislature of the State.

New Delhi;

NEELAM SANJIVA REDDY, President.

The 19th March, 1982.

[No. V. 11013/3/82-CSR]

New Delhi;

T. N. CHATURVEDI, Secy.

The 19th March, 1982.

आदेश

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1982

सं० का० वि० 257 (अ) :—राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित आदेश सर्व-साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है :—

भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंगीन मेरे द्वारा आज मार्च 1982 के उसीमर्चे दिन जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) के उपखण्ड (1) का अनुसरण करते हुए मैं एतद्वारा निदेश देता हूँ कि असम राज्य सरकार के सभी कृत्य और संविधान के अधीन या उस राज्य में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उस राज्य के राज्यपाल से निहित या प्रयोजन्य सभी शक्तियाँ जिन्हें राष्ट्रपति ने उक्त उद्घोषणा के खंड (क) के आधार पर स्वयं संभाल लिया है राष्ट्रपति के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अध्याधीन रहते हुए उक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा भी प्रयोजन्य होंगी।

नई दिल्ली,

नीलम संजीव रेड्डी, राष्ट्रपति

19 मार्च, 1982.

नई दिल्ली

[सं० 5/11013/3/82-सी० एम० आर०]

19 मार्च, 1982

त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी, सचिव

## ORDER

New Delhi, the 19th March, 1982

**G.S.R. 257(E).**—The following Order by the President is published for general information :—

In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of the Proclamation issued on this the 19th March, 1982, by me under article 356 of the Constitution of India, I hereby direct that all the functions of the Government of the State of Assam and all the powers vested in or exercisable by the Governor of that State under the Constitution or under any law in force in that State, which have been assumed by the President by virtue of clause (a) of the said Proclamation, shall, subject to the superintendence, direction and control of the President, be exercisable also by the Governor of the said State.

New Delhi;

NEELAM SANJIVA REDDY, President.

The 19th March, 1982.

[No. V. 11013/3/82-CSR]

New Delhi;

T. N. CHATURVEDI, Secy.

The 19th March, 1982.

